(ख) 1979-80 में जारी की गयी मांग की बकाया प्रविष्टियों में 85 प्रतिशत की कमी करना ;

(ग) आयकर की बकाया की वसूली के जटिल मामलों में अलग आयकर अधिकारियों की नियुक्ति करने की व्यवस्था की समीक्षा की जायगी तथा जहां कहीं भी व्यवहार्य होगा उनकी संख्या बढ़ाई जायगी ।

(3) कर की बकाया की वसूली की प्रगति पर मासिक निगरानी रखी जा रही है । इस संबंध में आंकड़े, आयुक्तों से तार मंगवाए जाते हैं और बोर्ड इस संबंध में उपयुक्त उपचारी कार्यवाई करता है ।

(4) कुछ आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में बकाया पड़ी अपीलों के निपटान के लिए अपीलीय तंत्र को सुदृढ़ किया जायगा ।

(5) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में विचाराधीन पड़ी ऐसी अपीलों की एक सूची, प्राथमिकता के आधार पर निपटान के लिए वर्ष 1979-80 में वित्त-मंत्रालय के माध्यम से न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को भेजी गयी थी जिनमें बकाया की बड़ी रकमें अन्तर्ग्रस्त थीं । आयकर आयुक्तों से निवेदन किया गया कि वे न्यायाधिकरण के स्थानीय पीठों के उपाध्यक्षों/सदस्यों के साथ सम्पर्क बनाये रखें । उनसे यह भी निवेदन किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से मिलें तथा उच्च मांग वाले अनिर्णीत मामलों के निपटान के लिए शीघ्र ही तिथि निर्धारित करने का निवेदन करें । चालू वित्तीय वर्ष में भी इसी तरह की कार्यवाई करने का निश्चय किया गया है ।

(6) आयकर आयुक्त के ओहदे का एक वसूली निदेशक कर की बकाया की वसूली विशेषत: 10 लाख रुपये और उससे अधिक के बकाया के मामलों में वसूली की प्रगति पर कड़ी निगरानी रख रहा है । उसके कार्य की प्रगति पर बोर्ड द्वारा निगरानी रखी जाती है ।

(7) परिसमापनाधीन कम्पनियों की और बकाया पड़ी कर की रकमों की वसूली में तेजी लाने के लिए कम्पनी कार्य विभाग ने बोर्ड के निवेदन पर 1979 में सभी सरकारी परिसमापकों के नाम अनुदेश जारी किया था जिसमें उनसे आयकर प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क स्थापित करने और आयकर अधिकारियों की अपेक्षित सूचना भेजने के लिए कहा गया था । इस संबंध में आयकर अधिकारियों को भी उपयुक्त अनुदेश जारी किए जा चुके हैं ।

(8) जनवरी, 1981 के दूसरे पखवाड़े में एक "कर की बकाया और वापसी निपटान पखवाड़ा" मनाया जाएगा जिसमें कर की बकाया को कम करने पर विशेष जोर दिया जाएगा ।

(9) बढा-चढा कर किये गये कर-निर्धारणों तथा उसके परिणामत: जमा हो गई कर की निरर्थक बकाया का निवारण करने की दृष्टि से, आयकर अधिकारियों को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144क के अधीन किसी निश्चित आय-सीमा से अधिक, एक तरफा कर-निर्धारण पूरा करने से पहले अपने निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा ।

Cash scarcity in branches of SBI in Manipur

2195. SHRI H. N. NANJE GOWDA:
SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to acute cash scarcity, the State Bank of India may have to close many of its Branches in Manipur; and

(b) if so, remedial action proposed to be taken by Government to overcome the situation?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): (a) and (b).

Towards the middle of this month reports were received about shortage of currency notes only in the Imphal branch of the State Bank of India and not in any other branch of SBI, in Manipur. The shortage was reported to have occurred because of difficulties in the escort and delivery of currency note consignments on account of disturbed situation in the Eastern States. After the receipt of the reports, currency consignments were rushed to Imphal branch of the SBI. According to the latest information received from the SBI the banking system is functioning normally and there is no apprehension of any bank closing down for want of cash.

Production of Thums Up & Non-payment of Excise Duty

2196. SHRI CHINTAMANI JENA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the quantity of "Thums Up" drink produced by Parle Breweries, Bombay, the manufacturers of "Thums Up" in 1979-80;

(b) whether the manufacturers of "Thums Up" have not paid excise duty on the Thums Up drink produced in 1979-80;

(c) if so, the total amount of excise duty paid in 1979-80;

(d) if not, the main reasons therefor; and

(e) whether any action has ever been taken by Government against them?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): (a) to (e). The information is being collected and a statement to this effect will be laid on the Table of the House.

West Bengal Unemployment Allowance Scheme

2197. SHRI HANNAN MOLLAH: SHRI INDRAJIT GUPTA: SHRI CHITTA BASU:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the West Bengal Government has proposed to the Central Government to pay 50 per cent of total amount of the unemployment allowance given to the unemployed persons in West Bengal; and

(b) if so, the decision of the Central Government in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): (a) Yes, Sir.

(b) The State Government was informed that, according to the Central Government, the endeavour of the State should be to use scarce financial resources for creation of additional gainful employment opportunities and not to give cash doles. It is however open to the State Government to formulate schemes for relief of unemployment within their own resources.

Payment to unemployed persons

2198. SHRI A. K. BALAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state whether Government propose to subsidise the States which have implemented the scheme of making payment to the unemployed persons?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): The Central Government is alive to the need for generation of opportunities for additional gainful employment. Apart from providing for on-going projects, the Central Budget for 1980-81 makes a provision of Rs. 340 crores for the new National Rural Employment